



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2019/माघ 10, 1940

No. 440]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2019/MAGHA 10, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2019

का.आ. 553(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 22.10.2018 के राजपत्र अधिसूचना का. आ. 5368(अ) के अधिक्रमण में, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, 'भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण', जोकि इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'प्राधिकरण की श्रेणी' के रूप में सरकार द्वारा गठित की गई है, को उसे होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:—

- (क) सरकार से सहायता अनुदान या ऋण/अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि;
- (ख) भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार बिल्डर/डवेलोपर, एजेंट या अन्य किसी हितधारक से प्राप्त शुल्क/शास्ति;
- (ग) उपर्युक्त (क) एवं (ख) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण—

- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

- (ख) कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए लागू समझी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए लागू होगी।

अनुसूची

क्र. सं.	भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण का नाम	पैन
(1)	(2)	(3)
1.	गुजरात भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण	AAAGG1260R
2.	छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण	AAAJC1049H
3.	राजस्थान भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण	AAAGR0430E

[अधिसूचना सं. 7/2019/फा. सं. 300196/38/2016-आईटीए-1]

राजराजेश्वरी आर., अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2019

S.O. 553(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Gazette notification S.O. 5368(E) dated 22.10.2018, the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Real Estate Regulatory Authorities' as specified in the schedule to this notification, constituted by Government in exercise of powers conferred under sub-section (1) of Section 20 of The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016) as a 'class of Authority' in respect of the following specified income arising to that Authority, namely:—

- Amount received as Grant-in-aid or loan/advance from Government;
- Fee/penalty received from builders/developers, agents or any other stakeholders as per the provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016;
- Interest earned on (a) & (b) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that each of the Real Estate Regulatory Authority—

- shall not engage in any commercial activity;
- activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment Year 2018-19 and shall apply with respect to the assessment years 2019-20, 2020-21, 2021-22 & 2022-23.

SCHEDULE

S.No.	Name of the Real Estate Regulatory Authority	PAN
(1)	(2)	(3)
1	Gujarat Real Estate Regulatory Authority	AAAGG1260R
2	Chhattisgarh Real Estate Regulatory Authority	AAAJC1049H
3	Rajasthan Real Estate Regulatory Authority	AAAGR0430E

[Notification No. 7/2019/F. No. 300196/38/2016-ITA-I]

RAJARAJESWARI R., Under Secy.

Explanatory Memorandum : It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.